

जहां लू लगने से गई 12 लोगों की जान, वहां नहीं है IMD की कोई वेधशाला



मुंबई। नवी मुंबई में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान भीषण गर्मी से 12 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों के बाद सरकार के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, जिस शहर में यह समारोह आयोजित किया गया था, वहां भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की कोई वेधशाला नहीं है जिसके आधार पर स्थानीय मौसम अलर्ट जारी किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आईएमडी ने अनुमान लगाया था कि नवी मुंबई के खारघर क्षेत्र में तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह अनुमान 35 किलोमीटर दूर मुंबई में

सांताक्रूज वेधशाला के आंकड़ों के आधार पर दिया गया था। हालांकि, तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तापमान नवी मुंबई के रबाले क्षेत्र में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) में पास की वेधशाला द्वारा दर्ज किया गया था। वेधशाला का संचालन ठाणे-बेलापुर औद्योगिक संघ द्वारा किया जाता है। आईएमडी वैज्ञानिक सुषमा नायर ने पीटीआई को बताया कि वेधशाला को 2017 में पुनर्जीवित किया गया था, जिसकी वजह से सामान्य गणना के लिए पर्याप्त अवलोकन नहीं है। नायर ने कहा, 'अगर हमारे पास उस स्थान के पास कोई वेधशाला नहीं है, जहां कार्यक्रम होना

है, तो हमारा प्रोटोकॉल है कि हम निकटतम वेधशाला के आधार पर पूर्वानुमान जारी करते हैं। इस मामले में यह सांताक्रूज वेधशाला थी।' मुंबई को छोड़ इसके उपग्रह शहरों में एक मजबूत मौसम संबंधी बुनियादी ढांचा नहीं है। मुंबई में मौसम डेटा प्राप्त करने के लिए आईएमडी के अलावा नागरिक निकाय का अपना तंत्र है। समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार प्रदान करने के लिए खारघर में होने वाले समारोह से पहले महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग ने आईएमडी से मौसम संबंधी जानकारी मांगी थी, जो उसे 12 अप्रैल को प्रदान की गई थी।

कई नेता हुए ये शामिल

महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने खारघर में समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने के लिए समारोह आयोजित किया था। इसके लिए विभाग ने आईएमडी से तापमान की जानकारी मांगी थी। जो विभाग ने 12 अप्रैल को दिया था। कार्यक्रम के दौरान लाखों लोग चिलचिलाती धूप में बैठे थे। आम जनता के अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे भी गर्मी में बैठे थे। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए वह भी रुमाल लेकर बैठे थे। पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे।

4.5 डिग्री से अधिक तापमान होने पर हीटवेव का अलर्ट

नायर ने कहा कि हमने अनुमान लगाया था कि सांताक्रूज के आधार पर खारघर में अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम आर्द्रता 65-75 प्रतिशत रहने का अनुमान था और न्यूनतम तापमान 55-65 प्रतिशत था। नायर ने कहा कि आईएमडी के पास रिपोर्टिंग के लिए नवी मुंबई के उस क्षेत्र में मौसम विभाग की कोई लैब नहीं है। रविवार को सांताक्रूज में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। यह सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस ही अधिक था। अधिकारी के अनुसार, सांताक्रूज में कोई लू की कोई संभावना ही नहीं थी। नायर के अनुसार, तापमान जब सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा होता है, तब आईएमडी हीटवेव का अलर्ट जारी करता है। रविवार को मुंबई के कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक था। वहीं, मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में तापमान सामान्य से भी कम था।

शैली ओबरॉय ने मेयर व इकबाल ने डिप्टी मेयर पद पर किया नामांकन

नयी दिल्ली, (वार्ता)। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ डॉ. शैली ओबरॉय ने मेयर और आले मोहम्मद इकबाल ने डिप्टी मेयर पद पर सोमवार को नामांकन किया।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और दिल्ली शिक्षा मंत्री आतिशी की उपस्थिति में डॉ. ओबरॉय और इकबाल ने नामांकन किया है। इसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनादेश नहीं मानती है। उनकी राजनीति खरीद-फरोख्त की है लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद

जिम्मेदारी मिली है तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद निगम की हालत क्या है ताकि उसको सुधारा जा सके। इसके अलावा शिक्षा मंत्री आतिशी स्कूलों की हालत देख रही हैं।

आप नेता ने कहा कि भाजपा जो भी हथकंडे अपनाना चाहे, अपना सकती है। पिछली बार उन्होंने तीन बार हंगामा किया और सदन के अंदर हिंसक प्रदर्शन किया।



केजरीवाल पर भरोसा जताया है। इसके जरिए दिल्ली मॉडल पर मुहर लगाई है। भाजपा के 15 साल के कुशासन को दिल्ली की जनता ने खत्म किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार डॉ. शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को क्रमशः मेयर- डिप्टी मेयर का प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने अभी नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को जबसे

उनका यही चरित्र है जिसे पूरे देश ने देखा था। सुश्री आतिशी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि भारी बहुमत से दोनों चुनाव जीतेंगे।

जिस तरह से पिछले कार्यकाल में तेज रफ्तार से काम हुए हैं, उसी तरह आगे भी होंगे। हमारे मेयर-डिप्टी मेयर एसी कमरों में नहीं रहते हैं, बल्कि फ्लॉड में घूमते हैं। वह कूड़े के पहाड़ से लेकर अलग-अलग वार्डों, स्कूलों और अस्पतालों में जाते हैं। इससे सिस्टम में एक फुर्ती आ गई है।

पीएम मोदी करेंगे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

नई दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव में दुनिया भर को बौद्ध जीवन दर्शन से जोड़ने और भगवान बुद्ध के विश्व शांति के संदेश को पहुंचाने के लिए 20-21 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन से फिलहाल चीन ने दूरी बना ली है।

इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म को मानने वाले जहां दुनिया भर के करीब 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, वहीं चीन का कोई प्रतिनिधि इनमें नहीं हिस्सा ले रहा है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के आयोजन



की जानकारी देते हुए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ और संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया

जा रहा है। इसके शुरूआती सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में दुनिया भर में बौद्ध धर्म मानने वाले करीब 30 देशों के 170 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही इस सम्मेलन में भारत के भी अलग-अलग बौद्ध मठों से जुड़े 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। दो दिवसीय इस सम्मेलन में अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा के साथ परिसंघों के प्रमुख का मार्गदर्शन और भविष्य की दिशा व योजना पर भी चर्चा होगी।

अतीक-अशरफ के शूटर लाए गये प्रतापगढ़ जेल

प्रताप गढ़ (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद व अशरफ पर प्रयागराज मेडिकल कॉलेज परिसर में दनादन गोलियां दागकर पूरे प्रदेश और देश को हिला देने वाली घटना को अंजाम देने वाले तीन शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि सिंह को आज कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतापगढ़ जिला कारागार लाया गया। प्रतापगढ़ जिला कारागार के जेलर राजेश पाण्डेय से मिली जानकारी के अनुसार तीनों शूटरों को प्रयाग राज के नैनी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच यहां जिला जेल में लाया गया है। इन तीनों को जिला जेल में दाखिल कर लिया गया है। पहले इन शूटरों को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा गया था लेकिन इस जेल में अतीक के कई समर्थक कैदी बंद हैं।

आवश्यक सूचना

'उत्तराखण्ड प्रहरी' के सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि आप अपने प्रिय अखबार 'उत्तराखण्ड प्रहरी' महाभियान में शामिल हो सकते हैं। आप अपने द्वारा लिखी गई कोई भी संरचना, कविता, कहानी, लेख या कार्यक्रम हमसे साझा कर सकते हैं। अच्छे लेख व कहानी को 'उत्तराखण्ड प्रहरी' में उचित स्थान दिया जाएगा। आप अपने प्रियजनों को जन्मदिन, सालगिरह या अन्य शुभ अवसरों पर बधाई संदेश भी दे सकते हैं।

आप हमें ईमेल

uttarakhandprahari19@gmail.com या
whatsapp no 8077771906 पर भी भेज सकते हैं।

संपादकीय

अतीक का 'हत्यावादी' अंत

माफिया अतीक अहमद की जिंदगी का यह सबसे नाटकीय घटनाक्रम रहा। पुलिस के सख्त पहरे और चौतरफा घेरेबंदी के बावजूद, किसी ने मीडिया का मुखौटा धारण कर, अतीक और उसके छोटे भाई अशरफ पर गोलियां चला दीं और कुछ ही सेकंड में जिंदगियां निष्प्राण हो गईं। माफिया के रूपक बने दोनों भाई मारे गए। गोलीबारी करने वाले 'जय श्रीराम' का उद्घोष करते रहे, जाहिर है कि वे किसी हिंदूवादी संगठन के सदस्य होंगे! यह हत्यावादी हमला भी किसी साजिशाना रणनीति का हिस्सा हो सकता है! अतीक और अशरफ को 'लाश' बनाने वालों ने आत्म-समर्पण भी कर दिया। उन पर हत्या का मुकदमा चल सकता है। साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट और सार्वजनिक हैं। उग्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग से जांच के आदेश दिए हैं। बेशक अतीक की माफियागिरी का फिलहाल अंत को चुका है, लेकिन उसके चार बेटे (दो बालिंग, दो नाबालिंग) पुलिस की गिरफ्त में हैं। जब भी वे जेल से मुक्त होंगे, क्या वे भी माफियागिरी का रास्ता अख्तियार करेंगे? क्या इस तरह अतीक और अशरफ की मौत भी एक सांप्रदायिक मुद्दा बन सकती है? क्या सपा, बसपा और अवैसी इस मौतकांड को 'मुस्लिमवाद' के तौर पर प्रचारित करेंगे? अतीक को मुलायम सिंह यादव और मायावती सरीखे नेताओं का संरक्षण हासिल था, जिसकी छाया में वह माफिया बनता चला गया।

अतीक के खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक केस बताए जा रहे हैं। करीब दर्जन भर राज्यों में अतीक की ठेकेदारी भी माफियागिरी की तर्ज पर चलती रही। उसने अपराध और कारोबार से करोड़ों रुपए अर्जित किए। उग्र सरकार का दावा है कि वह 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतीक की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। बुलडोजर से न जाने कितना नुकसान किया होगा, लेकिन इस माफिया कांड का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या किसी अपराधी की आपराधिक और दंडनीय नियति पुलिस और सरकार ही तय कर सकती है? दरअसल भारत के दंड-विधान और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो मुठभेड़ और मानवीय हत्या की इजाजत देता हो। हम मुठभेड़ या फांसी पर लटकाने की प्रक्रियाओं के खिलाफ हैं। हालांकि कानून में पुलिस को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो आत्मरक्षा या अपराधी के भाग जाने अथवा किसी अन्य अपरिहार्य स्थितियों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम हरेक मुठभेड़ या इस तरह की हत्या को 'फर्जी' या 'सांप्रदायिक' करार देने के भी पक्ष में नहीं हैं। हालांकि अतीक और उसके बेटे असद की हत्याओं के संदर्भों में सर्वोच्च अदालत के दिशा-निर्देश गौरतलब हैं। मुठभेड़ और हत्या होने के बाद धारा 176 के तहत, मामले की, अनिवार्य रूप से न्यायिक जांच की जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री का आदेश पर्याप्त है? मुठभेड़ हो, तो उसकी रपट धारा 190 के तहत अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों को भी इसकी रपट भेजी जानी चाहिए। मुठभेड़ के बाद प्राथमिकी तुरंत दर्ज की जानी चाहिए और उसे धारा 157 के तहत, बिना किसी देरी के, अदालत को भेजनी चाहिए। बुनियादी तौर पर यह मामला मुठभेड़ का है, क्योंकि 24 फरवरी के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सभी 6-8 आरोपितों को मुठभेड़ के जरिए या हत्या कर समाप्त किया गया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने 23 मार्च, 2022 को राज्यसभा को अवगत कराया था कि देश भर में बीते छह सालों के दौरान मुठभेड़ के 813 केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामले बीते दो साल में करीब 70 फीसदी बढ़े हैं। अप्रैल, 2016 के बाद से हर तीसरे दिन औसतन एक मुठभेड़ जरूर हो रही है।

अब रुपया लगाएगा नई छलांग

डा. जयंतिलाल भंडारी

देश की नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) एक अप्रैल से लागू की गई है। इससे निर्यात तेजी से बढ़ेंगे। जिस तरह नई विदेश व्यापार नीति से विदेश व्यापार रुपए में किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, उससे भारत का रुपया दुनिया के मुद्रा बाजार में नई छलांग लगाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिलेगी। यह कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया के 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार की सहमति बन चुकी है और रूस, श्रीलंका व मारीशस के साथ रुपए में व्यापार शुरू हो गया है। गौरतलब है कि पिछली विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी और इसके समाप्त होने की तिथि 2020 थी, लेकिन कोरोना वायरस आने के कारण सितंबर 2022 में इसे 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। अब सरकार ने नई एफटीपी नीति को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नए निर्देशों और नियमों के अनुरूप बनाया है। यदि हम नई विदेश व्यापार नीति की तस्वीर को देखें तो इसमें कई प्रमुख बातें उभरकर दिखाई दे रही हैं। पहले विदेश व्यापार नीति पांच वर्षों के लिए होती थी, लेकिन अब नई नीति की कोई अंतिम तारीख नहीं है। इसमें उपयुक्तता अनुरूप परिवर्तन किए जा सकेंगे। नई विदेश व्यापार नीति के तहत सरकार ने निर्यात के दायरे को बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब की स्थापना करने की घोषणा की है और वित्त वर्ष 2023-24 में 75 जिलों में एक्सपोर्ट हब बनाए जा सकते हैं।

इससे निर्यात से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दूर हो सकेगी। सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान का काम पहले ही पूरा कर चुकी है। जिला स्तर पर निर्यात सुविधा विकसित होने से उस जिले के उत्पाद को आसानी से निर्यात किया जा सकेगा। ऐसे प्रयास से सभी राज्यों को निर्यात में हिस्सेदार बनने का मौका मिलेगा और वहां रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने टाउंस ऑफ



एक्सपोर्ट एक्सीलेंस (टीईई) की लिस्ट में चार नए शहर शामिल किए हैं। फरीदाबाद को अपैरल, मुरादाबाद को हैंडीक्राफ्ट, मिर्जापुर को हैंडमेट कार्पेट और वाराणसी को हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट उत्पाद के लिए टीईई का दर्जा दिया गया है। इसके पहले 39 शहरों को टीईई का दर्जा प्राप्त है। ई-कॉमर्स के माध्यम से होने वाले निर्यात के प्रोत्साहन के लिए अलग से ई-कॉमर्स जोन की स्थापना का भी ऐलान किया गया है। कूरियर सेवा के माध्यम से होने वाले निर्यात की वैल्यू लिमिट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति खेप कर दिया गया है। ऐसे में ई-कॉमर्स निर्यात 2030 तक 200 से लेकर 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। खास बात यह भी है कि नई एफटीपी के तहत आवेदनों का डिजिटलीकरण किया जाएगा तथा आवेदकों को स्वचालन प्रणाली के जरिए मंजूरी दी जाएगी। पहले निर्यात संबंधी विभिन्न मंजूरीयों से तीन दिन से लेकर एक महीने का समय लगता था, अब यह मंजूरी एक दिन में मिलेगी।

निर्यातक खुद ही वस्तुओं को सत्यापित कर सकेंगे। निर्यात लाइसेंस शुल्क में कटौती की गई है। पहले शुल्क 1000 से 10000 रुपए देना होता था, अब केवल 100 से 5000 रुपए देने होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए शुल्क में भी बड़ी कटौती की गई है। मैनुफैक्चरिंग से संबंधित

उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अब निर्यातक उन वस्तुओं का निर्यात भी कर सकेंगे जिनके निर्यात पर भारत में प्रतिबंध होगा। निर्यातक देश में प्रतिबंधित वस्तुओं को किसी एक देश से खरीदकर दूसरे देश में बेच सकेंगे। निर्यातक पुराने सभी बकायों को विशेष रियायत स्कीम के तहत 30 सितंबर तक चुकाकर लाभान्वित हो सकेंगे। निश्चित रूप से इस समय जब नई विदेश व्यापार नीति लागू की गई है, तब वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत के निर्यात बढ़ने की कई अनुकूलताएं भी हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वर्ष 2021-22 में उत्पाद एवं सेवा निर्यात का जो मूल्य करीब 676 अरब डॉलर था, वह चालू वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 760 अरब डॉलर से भी अधिक हो सकता है। भारतीय उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। देश से उच्च इंजीनियरिंग निर्यातों, परिधान और वस्त्र निर्यात आदि से संकेत मिलते हैं कि यह धारणा धीरे-धीरे बदल रही है कि भारत प्राथमिक जिनसों का ही बड़ा निर्यातक है। अब भारत के द्वारा अधिक से अधिक मूल्यवर्धित और उच्च गुणवत्ता वाले सामानों का निर्यात भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि कोविड-19 के कारण भारत के सेवा निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कोविड-19 के बाद दो साल में कुल आईटी सेवाओं के निर्यात में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उत्तराखण्ड प्रहरी

कविता

अंतर्मन

जरूरी है कभी-कभी अपनी रूह से भी रु-ब-रू होना,

अपने अंतर्मन में झांकना और अपनी अंतर आत्मा को पहचानना।

हृदय में छिपे रहस्यों को जानना और चित्त में छिपे मेल को बाहर निकालना,

वयों भेजा है ऊपर वाले ने तुझे इस जहां में बस उस सही मकसद को जानना।।



सचिन बेदी अधिवक्ता, हरिद्वार

विश्वसनीयता की कसौटी पर भारतीय मीडिया

प्रो. सुरेश शर्मा

भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश को संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाने के लिए चार मुख्य एवं महत्वपूर्ण स्तम्भों विधानपालिका कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रेस यानी मीडिया का निर्माण किया गया। संविधान में इन सभी के कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं तथा ये चारों एक-दूसरे के बीच हस्तक्षेप नहीं करते। विधानपालिका देश के संचालन के लिए कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका के माध्यम से बनाए गए नियम या कानून सभी के लिए समान रूप से क्रियान्वित एवं लागू होते हैं। यह कानूनों को जनता में पहुंचाने, पालन करवाने तथा समान रूप से लागू करने का कार्य करती है। न्यायपालिका बनाए गए कानूनों की व्याख्या तथा कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान करती है। इससे कोई भी व्यक्ति शक्ति, प्रभाव या धन बल के आधार पर कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रेस यानी पत्रकारिता या मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मान्यता मिली है। यह लिखित एवं दृश्य एवं श्रव्य संसाधनों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका

पर नजर रखता है। मीडिया की नजर तीनों स्तम्भों के जिम्मेवारी, निष्ठा तथा पक्षपात रहित कार्य करने पर रहती है। मीडिया द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा जागरूकता के पश्चात निर्णय लेने की शक्ति जनता के विवेक तथा निर्णय पर निर्भर करती है। मीडिया जनता, चुने हुए प्रतिनिधियों, प्रशासन तथा न्यायिक व्यवस्था पर अपनी पैनी नजर रखते हुए सभी के बीच एक सेतु का कार्य करता है। लोकतंत्र का घेरा लोगों द्वारा बनाई गई विधायिका से चलकर कार्यपालिका, न्यायपालिका व मीडिया से होते हुए पुनः लोगों के पास ही आ जाता है।

भारत में इन सभी को मिलाकर एक मजबूत एवं सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। प्रेस, पत्रकारिता या मीडिया संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के तहत भारत के संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को संदर्भित करते हुए स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करती है और लोगों को सरकार या उसके विरुद्ध अपनी राय देने की अनुमति प्रदान कर लोकतंत्र को मजबूत करती है। भारत में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। देश के लोगों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और देश की अखंडता को

सुनिश्चित करने के लिए इसमें अनुच्छेद 19 (2) के तहत कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अनुच्छेद 19 में घोषणा के केंद्र में कहा गया है, 'हर किसी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में हस्तक्षेप के बिना राय रखने और किसी भी मीडिया माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है।' मीडिया के अधिकार 'फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन' के अन्तर्गत आते हैं। अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में मीडिया वन मलयालम चैनल के प्रसारण पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया। मीडिया को प्रेस की आजादी जरूरी है। देश के सामने सच बोलना प्रेस का कर्तव्य है तथा इससे राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना कोई सत्ता का विरोध नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता को बल देना हुआ यह फैसला ऐतिहासिक तो है लेकिन इसके साथ ही प्रेस को अपनी सीमाओं, मर्यादाओं तथा अधिकार क्षेत्र में रह कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी उतना ही आवश्यक है।

वैधानिक सूचना

उत्तराखण्ड प्रहरी के संपादन में हम प्रयासरत हैं कि हमारी ओर से खबर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। हमारी कोशिश है कि अखबार में छपी किसी खबर, रिपोर्ट, फीचर या लेख से व्यक्ति विशेष, संगठन या समुदाय की भावना को ठोस न पहुंचे। उत्तराखण्ड प्रहरी में प्रकाशित लेख, विश्लेषण और साधारण, ली गई सामग्री के विचार संबंधित लेखकों और रचनाकारों के निजी विचार हैं, न कि अखबार के। अतः सभी पाठकों से आग्रह है कि वे किसी सूचना, समाचार, विज्ञापनों आदि के आधार पर कोई फैसला करने से पहले तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। उसके लिए किसी भी प्रकार से लेखक, संपादक, प्रकाशक, प्रिंटर या विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तथा किसी भी कारोबारी और निज निर्णय के लिए उत्तराखण्ड प्रहरी जिम्मेवार नहीं होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने किया महाराष्ट्र के सहकारी बैंक व अस्पताल का भ्रमण

सोलापुर में 105 वर्ष पुराने जिला सहकारी बैंक की बारीकियों को जाना

सहकारी अस्पताल में डा. रावत ने परखी कैथ लैब व आईसीयू सुविधाएं



सुमित तिवारी, उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने महाराष्ट्र भ्रमण के दौरान आज सोलापुर में सहकारिता एवं स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न संस्थानों का भ्रमण कर उनकी बारीकियों को जाना। सोलापुर में उन्होंने 105 वर्ष पुराने जिला सहकारी बैंक का दौरा कर वहां के अधिकारियों के साथ बैठक कर सहकारिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की, इसके अलावा उन्होंने सोलापुर स्थित अश्विनी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल का भी भ्रमण कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सहकारिता एवं

स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाराष्ट्र में किये गये अच्छे कार्यों को उत्तराखंड में भी लागू किया जायेगा इसके अध्ययन के लिये शीघ्र ही स्वास्थ्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों का एक दल महाराष्ट्र भेजा जायेगा।

महाराष्ट्र राज्य के दौरे पर गये कैबिनेट मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि उन्होंने सोलापुर स्थित 105 वर्ष पुराने जिला सहकारी बैंक का दौरा कर बैंक की कार्यप्रणाली को बारीकी से जाना तथा वहां के अधिकारियों एवं स्टॉफ से बैंक के क्रियाकलापों एवं उससे



जुड़े, ग्राहकों के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर सहकारी बैंक के संचालन एवं ग्राहकों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। डॉ. रावत ने बैंक के अधिकारियों को बताया कि उत्तराखंड में भी सहकारी बैंक बेहतर की ओर अग्रसर है। प्रदेश के बैंकों में एनपीए कम करने के लिये प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया गया जिससे सहकारी बैंकों का एनपीए काफी कम रह गया है। इसी प्रकार सहकारी समितियों को

शतप्रतिशत कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है, जोकि सहकारिता के क्षेत्र में एक मिशाल है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने महाराष्ट्र सहकारी बैंक के शीर्ष अधिकारियों को पैक्स समितियों के क्रियाकलापों के अध्ययन को उत्तराखंड आने को आमंत्रित किया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री डा. रावत ने सोलापुर स्थित अश्विनी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल का भ्रमण कर वहां की चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कैथ लैब, आईसीयू व अन्य सुविधाओं का

अवलोकन करने के साथ ही अस्पताल के संचालन की कार्यप्रणाली को भी जाना। साथ ही उन्होंने वहां पर इलाज करा रहे मरीजों से बातचीत कर अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी हासिल की। डा. रावत ने बताया कि शीघ्र ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग एवं सहकारी विभाग के अधिकारियों का एक दल सोलापुर के कोऑपरेटिव हॉस्पिटल के अध्ययन को भेजा जायेगा ताकि भविष्य में महाराष्ट्र की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तराखंड में भी लागू किया जायेगा।

10000 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रशासनिक दफ्तर में पेशकार हुआ गिरफ्तार

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

रुड़की। उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो, हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने रुड़की में प्रशासनिक दफ्तर में एक पेशकार को किसान से ₹10000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, पेशकार किसान का काम करने के बदले में ₹10000 रिश्वत मांग रहा था जिसकी शिकायत किसान ने विजिलेंस से की थी।

आज टीम ने रिश्वत लेते हुए पेशकार को गिरफ्तार कर लिया है। वही बीती रात विजिलेंस टीम ने ज्वालापुर कोतवाली में तैनात एक दरोगा को भी 20000 ₹ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था हरिद्वार में एक दिन में ही विजिलेंस की दो



20000

रुपए की रिश्वत लेते हुए ज्वालापुर का दरोगा हुआ गिरफ्तार

कार्रवाई के बाद पुलिस और प्रशासन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

- ▶ 20 हजार की रिश्वत लेते दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा
- ▶ विजिलेंस ने इंद्रजीत सिंह राणा को रिश्वत लेते पकड़ा रंगे हाथ
- ▶ मामले में जांच कर रहे दरोगा ने आरोपी से 20 हजार की मांगी थी रिश्वत
- ▶ देहरादून विजिलेंस ने दरोगा को रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार
- ▶ ज्वालापुर कोतवाली में तैनात था इंद्रजीत सिंह राणा
- ▶ हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस पर दाग।
- ▶ रंगे हाथों पकड़ा गया दरोगा इंद्रजीत सिंह राणा।
- ▶ 20 हजार की रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार।
- ▶ देर रात तक ज्वालापुर कोतवाली में पूछताछ जारी।
- ▶ कई बड़ी मछलियों के नाम आए सामने।
- ▶ सीएम धामी ने लिया मामले का संज्ञान।

हरिद्वार ब्रेकिंग

आर्थिक वित्तीय स्थिति हेतु जी-20 देशों में पारस्परिक सहयोग' विषयक क्वीज प्रतियोगिता आयोजित

अलकनंदा टीम ने मारी बाजी



उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। एस.एम.जे.एन.पी.जी. कॉलेज में आज अर्थशास्त्र विभाग व आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में जी-20 के सन्दर्भ में विविध जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत "आर्थिक वित्तीय स्थिति हेतु जी-20 देशों में पारस्परिक सहयोग' विषयक क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में टीम-ए अलकनंदा के प्रत्युश दूबे, खुशी गुप्ता, तनीषा बुडाकोटी, विनय चौहान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सुनील कुमार बत्रा ने समस्त प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनायें देते हुए कार्यक्रम संयोजक रूचिता सक्सेना व कु. अन्तिमा त्यागी की प्रशंसा की। डॉ.बत्रा ने बताया कि जी 20 सम्मेलन में भारत का मुख्य एजेंडा रोजगार सृजन, स्थिर वित्तीय बाजारों और वैश्विक व्यापार व्यवस्थाओं के लिए स्थिर

टीम में सम्मिलित छात्र छात्रा प्रत्युश दूबे, खुशी गुप्ता, तनीषा बुडाकोटी, विनय चौहान ने जीती प्रतियोगिता

और सतत वैश्विक विकास पर केंद्रित है। जी 20 सम्मेलन में भारत आयात - निर्यात व्यापार और निवेश के अलावा गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर विशेष बल दिया गया है। डॉ. बत्रा ने इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र छात्राओं की मुक्त कन्ठ से प्रशंसा की।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय कुमार माहेश्वरी ने कहा कि प्रश्नों से ही छात्र-छात्राओं को बौद्धिक विकास होता है। अतः इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी निश्चित रूप से छात्र-छात्राओं के बौद्धिक विकास में सहायक होगी। क्वीज प्रतियोगिता में चार टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया टीम ए

अलकनंदा में प्रत्युश दूबे, खुशी गुप्ता, तनीषा बुडाकोटी, विनय चौहान, टीम बी ब्रह्मपुत्र में करिष्मा शर्मा, गौरव बंसल, रिचा उनियाल, वरुण कुमार, टीम सी कोवरी में अर्शिका वर्मा, भव्या भगत, शैफाली मानव, भावेश पंवार तथा टीम डी दामोदर में डिम्पल गोयल, हिमानी ठाकुर, अमूरुला सक्सेना तथा सत्यम जोशी आदि सहित प्रतियोगिता के अन्तिम दौर में कुल 16 प्रतिभागियों का चयन किया गया। निर्णायक मण्डल की भूमिका का निर्वहन शिक्षा विद संदीप रावत द्वारा किया गया।

इस अवसर पर मुख्य रूप से अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय कुमार माहेश्वरी, प्रो. तेजवीर सिंह तोमर, डॉ. नलिनी जैन, विनय थपलियाल, डॉ. सुषमा नयाल, डॉ. लता शर्मा, डॉ. मोना शर्मा, श्रीमती रिचा मिनोचा, डॉ. सुगन्धा वर्मा, डॉ. पूर्णिमा सुन्दरियाल, कु. वन्दना, योगेश्वरी, शाहिन सहित कॉलेज के अनेक छात्र-छात्रा उपस्थित थे।

24 घंटे तक लड़ी मृतक कर्मचारी की लड़ाई, तब मिला मुआवजा

गौरव कुमार, उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगजीतपुर में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज में काम करते समय हुई मजदूर की मौत के मामले से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की भी पोल खुली है। मजदूर की मौत के बाद उसे मुआवजे के लिए परिजन और अन्य कर्मचारियों ने 24 घंटे तक संघर्ष किया। जिसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी मुआवजा देने को राजी हुई। सोमवार की देर शाम को मुआवजा मिलने के बाद परिजन शव को लेकर बिहार रवाना हुए हैं। जानकारी के अनुसार जगजीतपुर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में वाइब्रेटर मशीन चलाते हुए करंट लगने से शुभंकर (24 वर्ष) पुत्र चली तरसादा निवासी ग्राम राजपुर पीएस महेशी जिला सहरसा बिहार 10 से 15 फीट नीचे जा गिरा था। सिर में गंभीर चोट आई थी। जबकि करंट से भी झुलस गया था। इसके बाद साथी कर्मचारी उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल ले गए थे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के



लिए भिजवा दिया था। रविवार की देर शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। जिसके बाद कर्मचारी शव को मेडिकल कॉलेज में ही लेकर एंबुलेंस से पहुंच गए थे। जहां उन्होंने एंबुलेंस को खड़ी कर हंगामा शुरू कर दिया था। कर्मचारी 12 से 15 लाख रुपए

मुआवजा मृतक के परिवार को देने की मांग पर अड़ गए थे। रात भर कर्मचारी संघर्ष करते रहे। लेकिन यशवंत इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी मुआवजा देने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इश्योरेंस के लिए बाद में क्लेम कर लिया जाए। लेकिन कर्मचारी

निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से कर्मचारी की मौत के मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी लापरवाही उजागर

करंट लगने से 10 से 15 फीट नीचे जाकर गिरा था कर्मचारी, सुरक्षा के नहीं थे कोई इंतजाम

रविवार की रात से लेकर सोमवार की दोपहर तक धरने पर बैठे रहे और मुआवजे की मांग पर पड़ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कंपनी और कर्मचारियों के बीच लिखित समझौता हुआ। करीब नौ लाख का मुआवजा मृतक के परिवार को दिया गया। जिसके बाद परिवार देर शाम को शव लेकर रवाना हो गया। दूसरी तरफ सवाल उठे हैं कि क्या अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर ऐसे ही लापरवाह बनी रहेगी या फिर उनके काम करने के दौरान सुरक्षा के इंतजाम अपनाएगी। यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

रानीपुर विधायक आदेश चौहान बने कर्नाटक चुनाव में चिकमंगलूर के जिला प्रभारी

हरिद्वार। हरिद्वार से रानीपुर विधायक आदेश चौहान को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में संगठन की ओर से बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कर्नाटक में चिकमंगलूर जिले का प्रवासी जिला चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है। वह आज तारीकेरे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा



प्रत्याशी डी एस सुरेश के नामांकन में शामिल रहे। संगठन के साथ-साथ उनके बेहतर चुनाव प्रबंधन को देखते हुए पार्टी ने पूर्व में भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी उनकी जिम्मेदारी लगाई जाती रही है। वह कर्नाटक चुनाव में चिकमंगलूर जिले के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र चिकमंगलूर, तारीकेरे, कुंडापुरा, मुदिगेरे एवं श्रीनगेरी में प्रवासी चुनाव प्रबंधन कार्य देखेंगे। 10 मई को कर्नाटक चुनाव में मतदान के बाद रानीपुर विधायक आदेश चौहान की उत्तराखण्ड वापसी होगी।

हरिद्वार के प्रथम महापौर द्वारा किया गया भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष का स्वागत

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। हरिद्वार प्रथम महापौर मनोज गर्ग द्वारा गोविंदपुरी स्थित अपने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नवजोत वालिया का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष नवजोत वालिया ने मनोज गर्ग का आशीर्वाद प्राप्त कर उनका आभार व्यक्त किया और आगे कार्य हेतु चर्चा की गई।



भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवजोत वालिया जगजीतपुर निवासी हैं। पार्टी ने इस बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जिला उपाध्यक्ष नवजोत वालिया ने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के लिए लगातार क्षेत्र में कार्य किए जायेंगे और आगामी चुनाव हेतु युवाओं को तैयार किया जाएगा। इस मौके करन वर्मा, मनोज चौहान, गौरव वालिया, सुनील पाल आदि उपस्थित रहे।

जुआ खेलते हुए चार आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2330 रूपये की नकदी बरामद की है। पुलिस की कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी नरेश राठौड़ ने बताया कि पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एसएम



डायवर्जन ठेके के पास जगजीतपुर में जुआ खेला जा रहा है। इसके बाद जगजीतपुर चौकी प्रभारी देवेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जुआ खेलते चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनके कब्जे से कुल रूपए 2330 रूपए व एक ताश की गड्डी बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। नितिन पुत्र मनीष कुमार निवासी पीठ बाजार जगजीतपुर थाना कनखल जनपद हरिद्वार, दुष्यंत कुमार पुत्र आशाराम निवासी ग्राम मानक जूड़ी थाना अमरोहा यूपी हाल निवासी वसंत विहार फेस 2 जमालपुर कला थाना कनखल जनपद हरिद्वार, ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम निवासी बैलमंडी जगजीतपुर थाना कनखल जनपद हरिद्वार, अनुज कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी राजा गार्डन जगजीतपुर थाना कनखल जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक देवेन्द्र तोमर चौकी प्रभारी जगजीतपुर, हेड कांस्टेबल होशियार सिंह, कांस्टेबल प्रलव चौहान व कांस्टेबल प्रवीण कुमार मौजूद रहे।

होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉ पवन सिंह डॉ पन्नालाल गौतम नेशनल अवार्ड एवं सम्मान पत्र से हुए सम्मानित

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर प्रयागराज में 9 अप्रैल को आयोजित होम्यो फ्रेंड्स के तत्वावधान में 18 वॉ नेशनल होम्यो फ्रेंड्स सांठिफिक कांग्रेस एवं अवॉर्ड सेरेमनी में हरिद्वार के होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉ पवन सिंह को सम्मानित किया गया। डॉ पवन सिंह गंगा सफाई के साथ समाजसेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उनके क्लिनिक पर गरीबों पर निशुल्क इलाज होता है।

विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर होम्यो फ्रेंड्स द्वारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 18 वॉ नेशनल होम्यो फ्रेंड्स सांठिफिक कांग्रेस एवं अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। जिसमें देश के जाने माने होम्योपैथी के विशेषज्ञों के साथ हरिद्वार के पवन होलीस्टिक केयर क्लिनिक एवं होम्योपैथिक स्टोर के संचालक डॉ पवन सिंह को प्रयागराज के हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शंकर यादव के कर कमलों द्वारा 'डॉ पन्नालाल गौतम नेशनल अवार्ड एवं सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के दौरान उनकी पुत्री लवीना सिंह, जोकि बीएचएमएस की द्वितीय वर्ष की चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर की छात्रा



नेशनल होम्यो फ्रेंड्स सांठिफिक कांग्रेस एवं अवॉर्ड सेरेमनी में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शंकर यादव ने किया सम्मानित

इसके अलावा डॉ पवन सिंह को होम्योपैथी से गरीबों की सेवा करने के लिए डॉ बीएन मुखर्जी मैमोरियल अवार्ड—2019 से सम्मानित किया गया था। वे कुष्ठ एवं असहाय लोक सेवा समिति से जुड़कर सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं।

समिति के माध्यम से गरीबों से राशन एवं अन्य सामग्री निरंतर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा करना है। डॉ पवन सिंह ने लंबे समय तक सरकारी सेवा दी। उन्होंने लोगों की सेवा का संकल्प लिया हुआ है।

समिति के माध्यम से गरीबों से राशन एवं अन्य सामग्री निरंतर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा करना है। डॉ पवन सिंह ने लंबे समय तक सरकारी सेवा दी। उन्होंने लोगों की सेवा का संकल्प लिया हुआ है।

कंपनियों के नतीजे तय करेंगे बाजार की चाल

मुंबई, एंजिसियां। वैश्विक बाजार की तेजी से स्थानीय स्तर पर हुई लिवाली की बदौलत बीते सप्ताह करीब एक प्रतिशत चढ़े शेयर बाजार पर अगले सप्ताह वैश्विक रुख के साथ ही कंपनियों के समाप्त वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के परिणाम का असर रहेगा। बीते सप्ताह बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 548.03 अंक अर्थात 0.92 प्रतिशत की छलांग लगाकर सप्ताहांत पर 60431 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 228.85 अंक यानी 1.3 प्रतिशत की तेजी लेकर 17828 अंक पर रहा। समीक्षाधीन सप्ताह में बीएसई की दिग्गज कंपनियों की तरह मझौली और छोटी कंपनियों में भी जमकर लिवाली हुई। इससे मिडकैप 369.51 अंक की बढ़त लेकर 24720.57 अंक और स्मॉलकैप 424.24 अंक चढ़कर 28149.58 अंक पर पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार, बीते कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन दोनों मानक सूचकांकों ने लगातार नौ दिनों की बढ़त दर्ज की और अंत में उच्च स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर 2020 के बाद से 30 महीनों में सूचकांकों ने सबसे लंबा लाभ दर्ज किया। बाजार सात सप्ताह के उच्चतम स्तर पर



पहुंच गया, जो 21 फरवरी 2023 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर समाप्त हुआ। सूचकांकों में तेजी का प्रमुख कारण अमेरिकी डॉलर और इसने उभरते बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की खरीददारी रुचि को बढ़ावा दिया है। स्थानीय स्तर पर मार्च में उपभोक्ता मूल्य आधारित खुदरा मुद्रास्फीति

(सीपीआई) फरवरी के 6.44 प्रतिशत से गिरकर 15 महीने के निचले स्तर 5.66 प्रतिशत पर आ गई। मुख्य रूप से बिजली, खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण जनवरी में 5.2 प्रतिशत की तुलना में फरवरी में देश का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) मामूली बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गया।

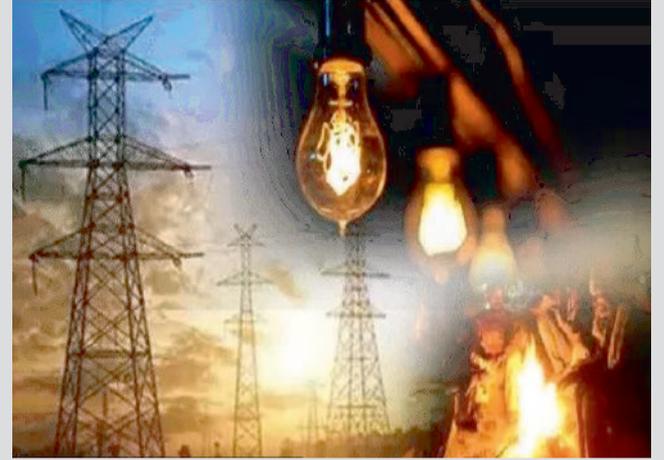
जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन की रैंकिंग में 'शीर्ष' पर मौजूद

जम्मू, 16 अप्रैल (भाषा) जम्मू-कश्मीर ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी को समर्थन देने वाले राज्यों की रैंकिंग में केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच शानदार प्रदर्शन किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त सचिव सौरभ भगत ने रविवार को बताया कि पिछले कुछ साल में जम्मू-कश्मीर में 84 स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। भगत ने कहा, "राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पांच श्रेणियों- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला, शीर्ष प्रदर्शन करने वाला, नेतृत्वकर्ता, आकांक्षी नेतृत्वकर्ता और उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में बांट दिया गया है।" उन्होंने कहा, "केंद्रशासित प्रदेशों, पूर्वोत्तर और एक करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में जम्मू-कश्मीर इस रैंकिंग

में 'शीर्ष' प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा जबकि मेघालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा।"

माइक्रोचिप्स और विनिर्माण के बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण (वीएलएसआई) के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तहत भगत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जम्मू में 'हिमालयन चैप्टर ऑफ नॉर्डन इंडिया' का उद्घाटन किया। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं शीर्ष संस्थानों को सेवाएं देगा। स्टार्टअप फर्मों को बदलावकारी बताते हुए आयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार बेहतर विचारों और समाधानों को आर्थिक सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीते वित्त वर्ष में बिजली की खपत 9.5 प्रतिशत बढ़कर 1,503.65 अरब यूनिट पर



नयी दिल्ली, (भाषा)। देश में बिजली की खपत बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सालाना आधार पर 9.5 प्रतिशत बढ़कर 1,503.65 अरब यूनिट (बीयू) हो गई। इसका मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के बीच बिजली की मांग बढ़ना है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में बिजली की खपत 1,374.02 अरब यूनिट थी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी बिजली आपूर्ति के आंकड़ों के अनुसार, एक दिन में अधिकतम बिजली की आपूर्ति पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 207.23 गीगावॉट हो गई, जो 2021-22 में 200.53 गीगावॉट थी। विशेषज्ञों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में बिजली की खपत और मांग में काफी सुधार देखने को मिलेगा। बिजली मंत्रालय ने इन गमियों में बिजली की अधिकतम मांग 229 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। मंत्रालय आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने का पहले ही निर्देश दे चुका है। इसके अलावा मंत्रालय ने

घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों से गमियों में बिजली की भारी मांग को पूरा करने के लिए मिश्रण के लिए कोयला आयात करने को कहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली की खपत में बढ़ोतरी से स्पष्ट पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियां सुधर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि मार्च में देश में बारिश नहीं होती, तो बीते वित्त वर्ष में बिजली खपत में वृद्धि दो अंक में होती। देश में बारिश की वजह से मार्च में बिजली की मांग प्रभावित हुई है। मार्च, 2023 में बिजली की खपत एक साल पहले की समान अवधि के 128.47 अरब यूनिट से घटकर 126.21 अरब यूनिट रह गई। अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक बिजली की खपत 2021-22 के स्तर को पार कर गई थी।

अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक बिजली की खपत 1,377.43 अरब यूनिट रही, जो पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में दर्ज 1,374.02 अरब यूनिट से अधिक है। विश्लेषकों का मानना है कि 2023-24 में बिजली खपत में वृद्धि दो अंक यानी 10 प्रतिशत से अधिक रह सकती है।



जलविद्युत संयंत्रों की बिजली में केंद्र हिमाचल का हिस्सा बढ़ाए: मुख्यमंत्री सुक्खू

शिमला, (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि विभिन्न जलविद्युत संयंत्रों से पैदा होने वाली बिजली के वितरण में राज्य का हिस्सा बढ़ाया जाए। सुक्खू ने केंद्रीय बिजली सचिव आलोक कुमार से काजा में मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सुक्खू ने राज्य सरकार और एसजेवीएनएल के बीच जलविद्युत परियोजनाओं- 210 मेगावाट की लुहरी-1, 172-मेगावाट की लुहरी-2, 382-मेगावाट सुन्नी और 66-मेगावाट के लिए हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर चिंता जताई। यहां जारी बयान के मुताबिक, सुक्खू ने कहा कि इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को की गई बिजली हिस्सेदारी की पेशकश अनुचित है और उन्होंने केंद्र सरकार से समझौतों की फिर से जांच करने का आग्रह किया। वर्तमान में हिस्सेदारी 12 फीसदी है। बयान के अनुसार, सुक्खू ने इन बिजली परियोजनाओं का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने के लिए 75 वर्षों की एक निश्चित समय सीमा तय करने का भी आह्वान किया।

एलआईसी दे रही लोगों को सुरक्षा कवच

ऊना। भारतीय जीवन बीमा निगम उपभोक्ताओं को आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। यह बात ऊना के दयाल रिवाज पैलेस में प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह एवं जागरूकता सेमिनार-2023 को संबोधित करते हुए दिल्ली से पधारे मुख्य वक्ता अमित शर्मा ने कहीं। संगोष्ठी में मार्च 2023 के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रदेश की 10 शाखाओं से 11 विकास अधिकारियों की टीम के 220 अधिकारियों को अचीवर्स अवार्ड से भी अलंकृत किया गया। इससे पहले निगम गीत भी गाया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए अमित शर्मा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को बीमा पॉलिसी प्रदान कर उनकी व उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का बड़ा दायित्व अधिकारियों के जिम्मे है। उन्होंने कहा कि एलआईसी के माध्यम से देश भर में 30 करोड़ से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर लोगों को जीवन बीमा के बारे में जागरूक किए जाने की जरूरत है। इस दिशा में अधिकारियों को काम करना चाहिए, तथा प्रत्येक नागरिक को जीवन



बीमा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।

उन्होंने एलआईसी के आकर्षक प्लान जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद, जीवन तरुण, जीवन उमंग तथा प्लानस के बारे में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इन प्लानस के माध्यम से उपभोक्ताओं को बच्चों की शिक्षा, बुढ़ापे में मदद के लिए रिटायरमेंट प्लान, कन्यादान योजना, स्वास्थ्य बीमा,

के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को जोनल लेबल पर अप्रैल से जून माह के लिए शुरु हुए जेडम ट्रॉफी 2023 प्रतियोगिता के लिए भी प्रेरित किया। इस अवसर पर विकास अधिकारी डीसी शर्मा, देवराज, मनोज कंवर, नवदीप चौहान, राहुल अत्री, सोमनाथ पाल, सुशील कुमार, विकास धीमान, विक्रम परमार, विपिन काशिव व विवेक वर्मा आदि मौजूद रहे।

रियल मैड्रिड के अश्वेत डिफेंडर के साथ नस्लीय दुर्व्यहार



मैड्रिड, (वार्ता)। रियल मैड्रिड के अश्वेत डिफेंडर एंटोनियो रुडिगर को कैडिज़ में घरेलू टीम के खिलाफ खेले गये स्पैनिश लीग मैच के बाद नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।

स्पैनिश मीडिया द्वारा रविवार को पोस्ट किये गये वीडियो में देखा जा सकता है कि रुडिगर मैच के बाद मैड्रिड के एक प्रशंसक को अपनी शर्ट भेंट कर रहे हैं, जबकि कैडिज़ सीएफ के प्रशंसक उनपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। रुडिगर ने कुछ प्रशंसकों के साथ शब्दों का आदान-प्रदान किया, जिसके बाद मैड्रिड के स्टाफ के दो सदस्य रुडिगर को दर्शकों से दूर ले गये। यह घटना कैडिज़ पर रियल मैड्रिड की 2-0 की जीत के बाद हुई। स्पैनिश फुटबॉल में इस

सीजन नस्लवाद की कई घटनाएं पेश आयी हैं। रुडिगर से पहले उनकी टीम के साथी विनीशियस जूनियर को भी कई मैचों के दौरान नस्लभेदी टिप्पणियों का निशाना बनाया गया है। इस महीने की शुरुआत में, विनीशियस ने मल्लोर्का के एक प्रशंसक के खिलाफ शिकायत की, जिस पर एक मैच में उसे बंदर कहने का आरोप लगाया गया था। इसी प्रशंसक पर एक अन्य लीग मैच में विलारियल मिडफील्डर सामू चुकुवेज़ का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया था।

वलाडोलिड ने हाल ही में विनीशियस के कथित मौखिक दुर्व्यवहार की जांच करते हुए 12 सीजन-टिकट धारकों को निर्लंबित कर दिया था।

किशन, सूर्यकुमार ने दिलाई मुंबई को जीत

मुंबई, (वार्ता)। खराब फॉर्म से गुज़र रहे ईशान किशन (25 गेंद, 58 रन) और सूर्यकुमार यादव (25 गेंद, 43 रन) की आतिशी पारियों से मुंबई इंडियन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को पांच विकेट से मात दी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर (51 गेंद, 104 रन) के विस्फोटक शतक की बदौलत 20 ओवर में 185 रन बनाये, हालांकि अन्य बल्लेबाजों की नाकामी के कारण उनका यह सैकड़ा काम न आया और मुंबई ने 17.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज किशन ने 25 गेंद पर पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 58 रन बनाये, जबकि रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने 25 गेंद पर चार चौकों और तीन छक्कों के साथ 43 रन की पारी खेली। मुंबई इस समय अंक तालिका में दो जीत और दो हार के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि केकेआर पांच मैचों में दो जीत और तीन हार के साथ पांचवें पायदान पर है। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज नारायण जगदीशन को शून्य रन पर आउट कर दिया, लेकिन अय्यर पहली ही गेंद से आक्रामक नज़र आये। सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ (12 गेंद, आठ रन) और कप्तान नीतीश राणा (10 गेंद, पांच रन) दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके, लेकिन अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केकेआर को पावरप्ले में 57 रन तक पहुंचाया। लगातार गिरते विकेटों के बीच केकेआर को साझेदारी की जरूरत थी जो शार्दुल ठाकुर और अय्यर के बीच देखने को मिली। अय्यर ने 23वीं गेंद पर चौका जड़कर अपना अर्द्धशतक पूरा किया और इसके बाद ठाकुर के साथ चौथे विकेट के लिये 50 रन जोड़े।

बीसीसीआई ने घरेलू आयोजनों की इनामी राशि बढ़ाई



मुंबई, (वार्ता)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को पुरुषों और महिलाओं के सीनियर घरेलू टूर्नामेंटों के लिये पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की।

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया कि पुरुषों की पुरस्कार राशि में जहाँ 60 प्रतिशत से 300 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी हुई है, वहीं महिलाओं के दो आयोजनों में 700 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी देखी गयी है। रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम की इनामी राशि दो करोड़ रुपये से बचाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गयी है, जबकि हारने वाली फ़ाइनलिस्ट और सेमीफ़ाइनलिस्ट टीमों को क्रमशः तीन करोड़ (पहले एक करोड़) और एक करोड़ (पहले 50 लाख) रुपये दिये जायेंगे। घरेलू एकदिवसीय टूर्नामेंट विजय हज़ारे ट्रॉफी

की इनामी राशि को 30 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है, जबकि उपविजेता को 15 लाख के बजाय 50 लाख रुपये दिये जायेंगे। घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की इनामी राशि में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है जहाँ विजेता को 80 लाख (पहले 25 लाख) और उपविजेता को 40 लाख (पहले 10 लाख) रुपये से पुरस्कृत किया जायेगा।

महिला सीनियर वनडे और टी20 ट्रॉफी चैंपियन और उपविजेता आखिरकार एक महत्वपूर्ण पुरस्कार राशि अर्जित करना शुरू कर देंगी। नतीजतन, महिला एकदिवसीय चैंपियन टीम रुपये 50 लाख (पहले छह लाख) कमाएगी जबकि टी20 चैंपियन टीम को 40 लाख (पहले पांच लाख) रुपये का इनाम दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय

संरा ने की सूडान में डब्ल्यूएफपी के तीन कर्मचारियों की हत्या की निंदा

खार्तूम, (वार्ता)। संयुक्त राष्ट्र (संरा) ने सूडान में युद्धरत बलों के बीच झड़पों में विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के तीन कर्मचारियों की हत्या की कड़ी निंदा की और कहा कि तीनों कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र एकीकृत सहायता मिशन (यूएनआईटीएएमएस) के प्रमुख वोल्कर पर्थेस ने रविवार को कहा कि एक दिन पहले उत्तरी दारफुर में संघर्ष में डब्ल्यूएफपी के तीन कर्मचारी मारे गए थे।

अल-अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत पर्थेस ने बयान में कहा, "संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय सुविधाओं के निर्माण की रिपोर्ट के अलावा, संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय सहायता एजेंसियों को दारफुर में कई जगहों पर संस्थानों के केंद्रों को लूटने की रिपोर्ट सामने आने से भी मैं बहुत चिंतित हूँ।" डब्ल्यूएफपी ने अपने तीन कर्मचारियों के मारे जाने के बाद सूडान में सभी कार्यों को अस्थायी रूप से निर्लंबित कर दिया है। डब्ल्यूएफपी के कार्यकारी निदेशक सिंडी मैक्केन ने एक बयान में कहा कि सूडान में सुरक्षा की बदलती स्थिति के



कारण हम सभी कार्यों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर हैं। इस बीच, सूडानी सेना ने देश का नियंत्रण हासिल करने के लिए राजधानी खार्तूम के पास प्रतिद्वंद्वी रैपिड एक्शन फोर्स के अर्धसैनिक अड्डे पर हवाई हमले किए हैं। सूडान में जंग शनिवार को जनरल अब्दुल फताह अल-बरहान के प्रति वफादार सैन्य इकाइयों और जनरल मुहम्मद हमदान दक्लुकी के नेतृत्व वाली रैपिड एक्शन फोर्स (आरएसएफ) के बीच शुरू हुई। अमेरिका, चीन, रूस, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ ने दोनों से युद्ध को तुरंत समाप्त करने की अपील की है।

भारत-अमेरिका के लोगों के बीच संबंध और मजबूत व बेहतर होंगे: व्हाइट हाउस अधिकारी

वाशिंगटन, (भाषा)। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और भारत के लोगों के आपसी संबंध जितने मजबूत हैं, उतने किसी और देश के लोगों के बीच नहीं हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हिंद प्रशांत समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने यह भी कहा कि बीते कुछ साल में दोनों देशों ने 'मजबूत रिश्ते' बनाए हैं जो और बेहतर होंगे।

वह देश की विविधता का जश्न मनाने के लिए भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित कर रहे थे। कैंपबेल ने कहा, "यह केवल विशिष्ट वर्ग की बैठक नहीं है। केवल प्रौद्योगिकी के कारण ये संबंध नहीं हैं। यह केवल सुरक्षा मुद्दों को लेकर भी नहीं है। यह एक ऐसा



रिश्ता है जो लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। अमेरिका और भारत के लोगों के आपसी संबंध जितने मजबूत हैं, उतने किसी और देश के लोगों के बीच नहीं हैं।"

उन्होंने कहा, "कई मामलों में, हमें सरकारों के तौर पर वास्तव में बीच में से

हटने की जरूरत है और अलग-अलग तरीकों से इन लोगों को साथ में काम करने देना चाहिए।" कैंपबेल ने कहा कि ऐसी दुनिया में जहाँ इतनी सारी चुनौतियां और कठिनाइयां हैं, वहाँ इस रिश्ते को बढ़ते और फलते-फूलते देखना अब्दुत है।

भारत दुनिया के साथ अपनी क्षमता और कामयाबी साझा करने को तैयार : भारतीय राजदूत

वाशिंगटन, (भाषा)। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि जी-20 के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत अपनी क्षमता और कामयाबी को दुनिया के साथ साझा करने को तैयार है। संधू ने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी सिर्फ दोनों देशों को ही फायदा नहीं देगी, बल्कि यह दुनियाभर के लिए अहम है। भारत ने पिछले साल दिसंबर में सालभर के जी-20 की अध्यक्षता लिए संभाली। वह इस साल सितंबर में नयी दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। जी-20 विश्व की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ 'इंडियन हाउस' में शनिवार को विशिष्ट भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करते हुए संधू ने कहा, "जी-20 के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में, हम अपनी क्षमता और सफलताओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं-टीकों और कौशल से लेकर डिजिटल सार्वजनिक लाभ तक और साथ ही हमने दूसरों से क्या सीखा है।"

उत्तराखण्ड प्रहरी छोटी खबरें



कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक चीता शिवपुरी में दिखा

शिवपुरी, (वार्ता)। मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक चीता निकलकर यहाँ के राई गाँव के खेतों में पहुँच गया। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि कूनो नेशनल पार्क से ओबान नाम का एक चीता बाहर निकलकर यहाँ के बैराड क्षेत्र स्थित राई गाँव के खेत में कल पहुँच गया। ग्रामीण लोग यह नजारा देखकर वह अपने घर की छत पर चढ़ गये। वन विभाग का अमला चीता को वापस उसे नेशनल पार्क में ले जाने के लिए प्रयास में जुटा हुआ है। इसके पहले भी एक चीता पार्क से निकलकर यहाँ पहुँच गया था और उसे पकड़कर वापस ले जाया गया। श्योपुर जिले का कूनो नेशनल पार्क शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग की सीमा से लगा हुआ है।

छात्रा का दो पुरुषों के साथ चाय पीना नागवार गुजरा, मामला सांप्रदायिक तनाव में बदला

खंडवा, (वार्ता)। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में एक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कल दोपहर दो विभिन्न वर्गों के दो लड़के और एक लड़की एक रेस्तरां में बैठकर साथ में चाय पी रहे थे। इसी बात को लेकर लड़की पक्ष के समुदाय के लोगों ने साथ में चाय पी रहे दूसरे पक्ष के युवकों के साथ मारपीट कर दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। ये मामला देर रात सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। देर रात एक पक्ष के लोग एकजुट होकर मोघट थाने पहुँचे और नारेबाजी करने लगे। कुछ लोगों ने थाने पर हल्का पथराव भी किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। तनाव ज्यादा फैलने से बचने के लिए जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि दोपहर में दोनों पक्ष की ओर से थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी थी, लेकिन देर रात कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और थाने पर आकर दबाव बनाया, जिसे पुलिस ने तुरंत ही नियंत्रित कर लिया। शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसलिए शहरी क्षेत्र में धारा 144 लगाई है।

रानी कमलापति पर बयान को लेकर माफी मांगें कमलनाथ : गृह मंत्री

भोपाल, (वार्ता)। मध्यप्रदेश में गोंड रानी कमलापति पर पिछले तीन दिन से चल रही राजनीति के बीच प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके बयान को लेकर माफी की मांग की है। डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि वे रानी कमलापति के लिए श्री कमलनाथ द्वारा दिए गए बयान की निंदा और भर्त्सना करते हैं। श्री कमलनाथ को इस बयान पर सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद अंबेडकर जयंती के दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह के बयान से शुरू हुआ था। डॉ सिंह ने उस दिन अपने बयान में कहा कि रानी कमलापति कौन हैं, वे नहीं जानते। उनके इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उन पर हमला बोला। श्री चौहान ने कहा कि केवल एक खानदान का नाम जपने वालों को कम कम से कम प्रदेश और आदिवासी भाई-बहनों की गौरव, महिला रानी कमलापति का अपमान नहीं करना चाहिए। यह अपमान प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों और एक प्रतापी महिला का अपमान है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने इसी संदर्भ में संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोज-रोज नए और 'फर्जी' नाम लेकर आ रही है।

पंच क्रांति के जरिए प्रदेश सरकार करेगी समाज के सभी वर्गों का कल्याण: शिवराज

ग्वालियर, (वार्ता)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 'अम्बेडकर महाकुंभ' में कहा कि इस सुअवसर पर हम प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये 'पंच क्रांति' की बात करने आए हैं। पंच क्रांति में शिक्षा की क्रांति, रोजगार की क्रांति, आवास अर्थात् रहने के लिये जमीन की क्रांति एवं सभी वर्गों के सम्मान की क्रांति शामिल है।

चौहान ने ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर धाम और संस्थान स्थापित करने के लिये स्थल उपलब्ध कराने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से समस्त पिछड़ी उप जातियों के अलग-अलग बोर्ड बनाने की घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहोगे तो आगे बढ़ोगे। इसी भाव के साथ प्रदेश सरकार ने शिक्षा की क्रांति के तहत श्रमोदय विद्यालय और ज्ञानोदय जैसे विद्यालय खोले हैं। छात्रावासों की स्थापना की है। साथ ही यदि किसी बच्चे को छात्रावास



उपलब्ध नहीं हो पाता तो कमरे का किराया भी सरकार भर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों और विदेश में पढ़ाई की फीस भी सरकार भर रही है। प्रदेश में अब हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई है। कायाकल्प अभियान में छात्रावासों की व्यवस्था बेहतर की जा रही है।

चौहान ने कहा कि प्रदेश में दूसरी

क्रांति रोजगार की क्रांति के रूप में चल रही है। प्रदेश में एक लाख 24 हजार पदों पर शासकीय भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को संत रविदास स्व-रोजगार योजना में एक लाख से 50 लाख एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से एक लाख रूपए तक का ऋण-अनुदान उपलब्ध करा रही है। पढ़े-लिखे बच्चों को अलग-अलग औद्योगिक

सेक्टर का काम सिखाने के साथ-साथ हर बच्चे को 8 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय भी दे रही है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में तीसरी क्रांति आवास अर्थात् रहने के लिये जमीन की क्रांति है। गरीब व्यक्ति के लिए रहने के लिए भूमि और आवास की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में सरकार द्वारा हर गरीब परिवार को रहने के लिए भूखंड का पट्टा दिया जा रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बहनों का सशक्तिकरण चौथी क्रांति है। लाइली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, संबल योजना, पंचायत निर्वाचन में महिलाओं को आरक्षण, शिक्षकों और पुलिस की भर्ती में आरक्षण, रजिस्ट्री स्टॉप शुल्क में छूट और अब लाइली बहना योजना से बहनों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है। समाज में उनका सम्मान बढ़ा है और वे सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही हैं। लाइली बहना योजना में आगामी 10 जून से बहनों के खाते में एक हजार रूपए पहुँचाए जाएंगे।

भाजपा कद्दावर नेता शेठार ने कांग्रेस का दामन थामा

बेंगलुरु, (वार्ता)। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कद्दावर नेता जगदीश शेठार सोमवार को यहां औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये। श्री शेठार ने रविवार को भाजपा का दामन छोड़ दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने उनका स्वागत किया। श्री शेठार आज सुबह बेंगलुरु में कां ग्रे स कार्यालय पहुंचे।



शिवकुमार ने कहा, "जगदीश शेठार की ओर से कोई मांग नहीं की गयी है, हम उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उन्हें (जगदीश शेठार) पार्टी के सिद्धांतों और नेतृत्व के अनुसार चलना होगा। हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं और इसे केवल कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है।"

इस बीच रविवार को प्रदेश भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा ने विधान चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी छोड़ने के श्री शेठार के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि वह उन्हें माफ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि श्री शेठार के इस तरह के कदम से उन्हें तकलीफ पहुंची है।

तीस लाख लेपटॉप निर्माण की नई इकाई लगेगी: सखलेचा

नीमच, (वार्ता)। मध्यप्रदेश के एमएमएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश के हर घर से एक व्यक्ति को डिजिटली साक्षर बनाया जाएगा। प्रदेश में 30 लाख लेपटॉप निर्माण की नई यूनिट भी प्रारंभ की जा रही है।

सखलेचा ने यह बात आज नीमच जिले के जावद में एमएमएमई विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण आधारित एमएमएमई की स्थापना पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला एवं उन्नत कृषकों की संगोष्ठी के शुभारंभ समारोह में कही। विधायक दिलीप सिंह परिहार, विधायक मनासा अनिरुद्ध मारू, इन्टेल कंपनी के पूर्व वाइस प्रेसीडेंट सी एस राव, ट्रोपोलाइट फूड इंडस्ट्रीज ग्वालियर की डॉ सोनाली सक्सेना, डॉ राजीव त्यागी, ईएण्डवाय के प्रतिनिधि सुनीलकुमार साई, सीएफटीआरआई मैसूर की डायरेक्टर

श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, वैज्ञानिक डॉ. उमेश हैदर, डॉ प्रवीणसिंह नेगी, डॉ आर बी श्रीधर सहित कई वैज्ञानिक, उद्योगपति, नव-उद्यमी, एवं प्रगतिशील कृषक उपस्थित थे।

एमएमएमई मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। नीमच जिले में एक वर्ष में 196 नये उद्योग स्थापित हुए हैं, साथ ही जिले में पाँच नये औद्योगिक क्लस्टर बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि जिले में उन्नत कृषि को देखते हुए खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों की नई श्रृंखला स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। विधायक मनासा अनिरुद्ध मारू ने कहा कि नीमच जिले में कृषि आधारित उद्योगों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बेंगलुरु से विशेष रूप से आए इन्टेल के पूर्व वाइस प्रेसीडेंट सी एस राव ने कहा कि आज डिजिटल इण्डिया काफी महत्वपूर्ण है। हम कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से लेपटॉप तैयार कर रहे हैं।

खट्टर को दिये गये हर पत्र पर कार्रवाई होगी, अधिकारियों की जवाबदेही तय

चंडीगढ़, (वार्ता)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को की गयी जनता की कोई भी शिकायत अब जाया नहीं होगी तथा इस सम्बंध में हर ऐसी शिकायत या सुझाव के लिये अधिकारियों को जबाबदेही तय कर दी गई है।

राज्य सरकार ने आम जनता की दुख तकलीफें दूर करने के लिए सीधे मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाने के लिए 25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस पर सीएम विंडो शुरू की थी जिसके प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ा था और गत साढ़े आठ वर्षों में लगभग 13 लाख शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक



पहुँचाई गई हैं। इनमें से अधिकांश का समाधान निर्धारित समयावधि में हुआ है। सीएम विंडो के लिए सभी जिला लघु सचिवालयों, उपमंडल कार्यालयों तथा मंत्रियों के कैब ऑफिस और कार्यालयों

में शिकायत लेने के लिए काउंटर खोले गए थे, जो काफी कारगर सिद्ध हुए। इनके माध्यम से ऐसी शिकायतों और समस्याओं का समाधान हुआ जिनके बारे लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया

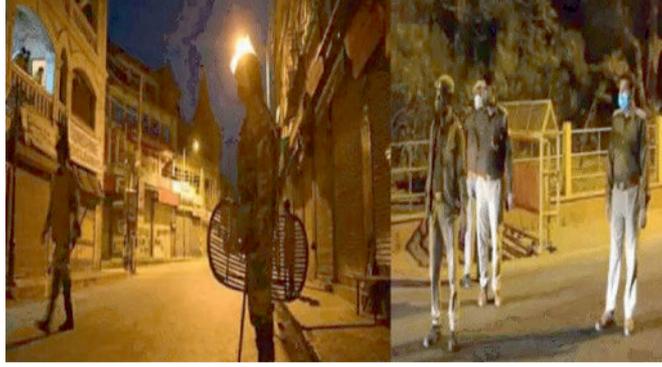
था। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने आम जनमानस की दुख तकलीफ को और नजदीक से समझने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। खट्टर ने अपने इस कार्यक्रम के तहत भिवानी तथा पलवल जिलों के लगभग दो दर्जन गाँवों के लोगों के बीच बैठकर बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि सीएम विंडो पर शिकायतें देने के बावजूद भी उनके कागज नहीं मिल रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो प्रणाली में ही जनसंवाद मॉड्यूल विकसित किया जाए जिसकी विधिवत

इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक लगा कर्फ्यू

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल जिला प्रशासन ने जिले में बाघ के आतंक को देखते हुए रिखणीखाल व धूमाकोट तहसील के दर्जनों गांवों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा 17 और 18 अप्रैल को इन दोनों तहसीलों के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। रिखणीखाल ब्लाक के ग्रामपंचायत मेलधार के डल्ला गांव में गत दो दिन पहले बाघ के हमले में हुए वृद्ध की मौत के बाद वन विभाग ने हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगा दिया है। रविवार को आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाया गया, जिसमें पडियारपाणी गांव में भी एक बाघ की मूवमेंट कैमरे में कैद हुई है।

ग्राम पंचायत मेलधार के प्रधान खुशेंद्र सिंह ने बताया कि बाघ के हमले में वृद्ध की मौत के बाद आसपास के गांवों में दहशत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग के कर्मी बंदूकों के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित गांव के रास्तों में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए 10 स्ट्रीट लाइटें दी गई हैं। जो कि रविवार को जुई गांव पहुंच गई है। स्ट्रीट लाइटों को प्रभावित गांव तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर, गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने



बताया कि हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगा दिया गया है। रविवार को बाघों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए क्षेत्र में ड्रोन उड़ाया गया, जिसमें पडियारपाणी गांव में भी एक बाघ की मूवमेंट नजर आई है।

जिला प्रशासन के आदेश के बाद शनिवार को स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब सोमवार से क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल खुलने हैं। ऐसे में अभिभावकों में अपने पाल्यों को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्राम प्रधान खुशेंद्र सिंह ने बताया कि अभी हमलावर बाघ नहीं पकड़ा गया है और बाघ की

मूवमेंट गांव के आसपास लगातार बनी हुई है। बाघ की सक्रियता को देखते हुए जिला प्रशासन से राप्रावि डल्ला, जुई, दियोढ, गाड़ियों पु ल, मेलधार, रजबो, द्वारी पैनों, छड़ियान, नावे तल्ली, चिलाउ एवं राउप्रावि

मेलधार, सिलगांव और राजकीय हाईस्कूल गाड़ियोंपुल, जीआईसी पैनों, राप्रावि कांडा राजकीय

जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित गांव के रास्तों में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए 10 स्ट्रीट लाइटें दी गई हैं। जो कि रविवार को जुई गांव पहुंच गई है। स्ट्रीट लाइटों को प्रभावित गांव तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हाईस्कूल कांडा, राप्रावि कोटड़ी, राजकीय कन्या हाईस्कूल कोटड़ी को सोमवार को भी बंद रखने की मांग की गई है। उधर, खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि अभी जिला प्रशासन से सोमवार को प्रभावित क्षेत्र के विद्यालयों को बंद रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने पर स्कूलों को बंद रखा जाएगा।



आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण नीति निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण : योगेन्द्र सिंह नेगी

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। दून विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल ने ब्रिलिका सर्विसेज के सहयोग से आज विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए डेटा एनालिसिस परिचय और कार्यन्वयन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। ब्रिलिका सर्विसेज के संस्थापक और निदेशक योगेन्द्र सिंह नेगी एवं प्रकाश कांडपाल तकनीकी प्रशिक्षण प्रबंधक



ने डेटा एनालिसिस पर विस्तार से चर्चा करते हुए आज के प्रतिस्पर्धी समय में इसकी अति आवश्यकता है और विद्यार्थियों को इसके प्रयोग की विधियों से परिचित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण नीतियों के निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण है। चाहे सरकारी नीति का निर्माण हो या कॉर्पोरेट जगत में निर्णय लेना हो, उसके लिये आवश्यक है कि आंकड़ों का सही एवं वैज्ञानिक विधि से संकलन किया जाय और उचित विधि से संकलित आंकड़ों का विश्लेषण भविष्य के लिये पूर्वानुमान

करने के साथ ही उचित नीति निर्माण में सहायक होता है। उन्होंने डेटा एनालिसिस की संरचना पर प्रकाश डाला व इसके कार्यान्वयन व महत्वपूर्ण पहलुओं व विस्तार से चर्चा की। सभी छात्रों ने इस कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर

दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा दंगवाल ने आयोजकों को बधाई दी एवं भविष्य में इस तरह के आयोजन में भाग लेने के लिये सभी छात्रों को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन प्लेसमेंट कॉर्डिनेटर डॉ प्राची पाठक ने किया। अधिष्ठाता छात्र कल्याण व प्रबन्ध संकाय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एच0सी0 पुरोहित ने कहा कि छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिससे विद्यार्थियों के कौशल विकास को बल मिलेगा। इस अवसर पर छात्र परिषद के अध्यक्ष आकाश नेगी, महा सचिव आशुतोष जायरा, कार्यक्रम के छात्र वालंटियर डॉली चौधरी, करन बिष्ट, प्रियंका जोशी, राहुल लोहानी सहित विभिन्न संकाय व स्कूल के कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।



दुनिया को राह दिखा सकती है भारत की मोबाइल क्लीनिक पहल

पणजी, पीटीआई। भारत ने दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल तरीकों को सक्रियता से अपनाया है। यहाँ अपनाई गई मोबाइल क्लीनिक की व्यवस्था पूरी दुनिया को राह दिखा सकती है। आपात स्थितियों से जूझ रहे देशों में इससे बड़ी राहत मिल सकती है। यूनिसेफ-न्यूयार्क के सीनियर एडवाइजर हेल्थ डा. लक्ष्मी एन बालाजी ने यह बात कही। वह भारत की अध्यक्षता में जी20 देशों की दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे हैं। सोमवार से शुरू हुई इस तीन दिवसीय बैठक में विभिन्न देशों के 180 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने बच्चों के नियमित टीकाकरण समेत विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों में मोबाइल स्वास्थ्य पहल को अपनाया है। मोबाइल हेल्थ की प्रक्रिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाया जाता है। इनमें टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और कुछ आवश्यक दवाओं की आपूर्ति तक शामिल हैं।

डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था ने निभाई अहम भूमिका

बालाजी ने कहा कि महामारी के दौरान आनलाइन कंसल्टेशन, कोविड टीकाकरण और जांच आदि के लिए कई डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाया गया। महामारी की चुनौतियों के बीच दूरदराज के क्षेत्रों तक कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविन पोर्टल के माध्यम से



सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को टीका लगे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कारगर व्यवस्थाबालाजी ने कहा कि मोबाइल क्लीनिक की मदद से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जा सकता है, जहाँ के लोग किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नाव के जरिये आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जैसे अशांत क्षेत्रों में कोई मोडिफाइड स्कूटर या रिक्शा किसी गर्भवती महिला के लिए एंबुलेंस की भूमिका निभा सकता है। ऐसे कई छोटे-छोटे प्रयास अच्छे नतीजे दे सकते हैं। डिजिटल दूरी को पाटना भी जरूरी बालाजी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल

सेवाओं के बढ़ते प्रयोग के साथ ही डिजिटल दूरी को पाटने की वकालत भी की। उन्होंने कहा, 'हमें ध्यान देना होगा कि समाज में डिजिटल डिवाइड भी है। बड़ा वर्ग है जिसके पास फोन और इंटरनेट नहीं है। महिलाओं के मामले में ऐसा ज्यादा है। इस पर ध्यान देना होगा। दुनियाभर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुल कार्यबल में करीब 67 प्रतिशत महिलाएं हैं। डिजिटल को अपनाते समय इसे भी ध्यान में रखना होगा।'

अन्य सेक्टर को भी शामिल करना होगा

बालाजी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल को अपनाते हुए शिक्षा, जल एवं स्वच्छता जैसे अन्य सेक्टर को भी इसमें शामिल करना चाहिए। डिजिटल व्यवस्था में कोडिंग ओपन-सोर्स पर हो, जिससे विभिन्न देश अपने अनुरूप थोड़े बदलाव से ही इन्हें प्रयोग करने में सक्षम हो सकें।